

07.07.2023 मंत्रायलिक कर्मचारियों की सामूहिक अवकाश व हड़ताल समाप्त होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलान्त उपस्थित। वकील अपीलान्त की प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व मूल अपील की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्त ने बताया कि भूमि खसरा नम्बर 1351, 1353 में अपीलान्त काफी समय पूर्व से आवासीय मकान बनाकर रह रहा है। बिजली कनेक्शन ले रखा है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार कार्यालय नीमकाथाना में पेश की है एवं उसी रिपोर्ट के अनुसार नोटिस जारी कर अपीलान्त के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया जो बिना जाँच किए किया गया है। उसे निरस्त किया जावे। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है। जिसमें ना तो नजरी नक्शा बनाया ना ही कहीं यह दर्शाया कि अतिक्रमण कहा कर रखा है। ना ही कोई रिपोर्ट में नाप-चोक व लम्बाई चौड़ाई की सीमा का अंकन किया है। अपील के साथ मियाद अधिनियम अन्तर्गत धारा 5 का प्रार्थना-पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। जो विलम्ब की क्षमा करते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अपील की अन्दर मियाद मानते हुए स्वीकार की जावे एवं तहसीलदार नीमकाथाना का आदेश दिनांक 07.09.2018 अपास्त किया जावें।

वकील अपीलान्त कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

मूल अपील की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का भूदौली द्वारा जो धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट तहसील कार्यालय में पेश की गई है। जिसमें अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1351 व 1353 किसम चारागाह में रकबा 0.0225 है0 में आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया है। तहसीलदार कार्यालय द्वारा नोटिस जारी होने पर अपीलान्त द्वारा जवाब व दस्तावेज पेश किये हैं। जो पत्रावली में शामिल है। पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के



25/7/23
जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

तारीख
दुकम

अवलोकन से पाया गया कि प्रस्तुत रिपोर्ट के पिछे जो नजरी नक्शा तैयार किया जाता है या बनाया जाता है को नहीं बनाया गया एवं ना ही रिपोर्ट के पिछे चारो दिशाओं का माप अंकित किया है जबकि रिपोर्ट के पिछे नक्शा तैयार कर उसमे अतिक्रमण रकबे को चिन्हित किया जाता है जो नहीं किया गया है।

इससे यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश कि गई है जो मौके पर जाकर तैयार नहीं कि गई है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें भी इन बिन्दुओं की जाँच किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इस आधार पर प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यो कि पुष्टि होती है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने से स्वीकार कि जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय के मुकदमा नम्बर 27/2018 उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल निर्णय दिनांक 07.09.2018 को अपास्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि मौके पर जाकर अतिक्रमण रकबे की नाप-चोक की जावे एवं इसी के साथ नजरी नक्शा तैयार कर उसके चारो दिशाओं का माप-चोक अंकित कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जावे एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी कि जावें। आदेश आज दिनांक 07.07.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।




(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला क्लर्क
एवं आति: जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)